सार संक्षेप

अमेरिका को आम निर्यात कम

वाशिंगटन ◆ अमेरिका को निर्यात किया जाने वाला आम अब कम होता जा रहा है। वाणिज्य सचिव राहुल खुल्लर ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बीते दो-तीन सालों में 20 लाख डॉलर की कीमत के आम अमेरिका को निर्यात किये जा रहे हैं। अमेरिका को निर्यात किये जाने वाल आम की मात्रा में कमी का कारण यह है कि अमेरिकी इंस्पेक्टरों द्वारा आम में रेडिएशन को चेक किया जा रहा है। इस कारण से न केवल आम की लागत बढ़ती जा रही है बल्कि आम की पूरी निर्यात प्रक्रिया ही धीमी होती जा रही है। 20 लाख डॉलर की कीमत के आम का निर्यात करने में 3 लाख डॉलर की जांच लागत आती है जो बहुत ही अधिक है।

बहरीन में भारतीयों को सलाह

नई दिल्ली ◆ बहरीन में रहने वाले भारतीयों को सलाह दी गई है कि वे घर से ना निकलें और ज्यादा से ज्यादा राशन इकट्ठा करके रखें जिससे उन्हें फायदा हो। बहरीन में भारत के राजदूत मोहन कुमार ने वहां की स्थिति पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि स्थिति तनावपूर्ण तो है पर शांत है। ऐसे में ज्यादा राशन इकट्ठा करके रखने की जरूरत है जिससे घर में बंद रहकर काम चलाया जा सकता है। कुमार ने उन भारतीयों को यह सलाह भी दी है कि जिनकी जरूरत फिलहाल बहरीन में नहीं है वे देश वापस लौटने की सोचें। साथ ही समस्त भारतीयों को अपने रहने सहन को साधारण बनाकर रखना चाहिए जिससे वे हमले का शिकार न बन सकें।

वीजा पर जताई असहमति

वाशिंगटन ◆ भारत ने अमेरिका से एच 1बी और एल1 वीजा पर अपनी असहमतियां जता दी है। केंद्रीय वाणिज्य सचिव राहुल खुल्लर ने कहा कि देश ने ऐसे वीजा मसले पर अपना पक्ष रख दिया है। सिर्फ आश्वासन से इस मसले का समाधान नहीं किया जा सकता। अगर परेशानियों को दूर नहीं किया गया तो समस्याएं और भी ज्यादा बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि भारतीयों को एच1बी और एल1 वीजा को लेकर खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिससे यह जरूरी है कि भारतीयों की जरूरतों को समझा जाये।

कर संग्रहण में 26% ग्रोथ

कोलकाता ◆ देश का कर राजस्व वित्त वर्ष 2010-11 के 12 मार्च तक अच्छा रहा। इस दौरान बीते साल की समान अवधि की तुलना में तकरीबन 26 फीसदी का ग्रोथ दर्ज किया गया है। राजस्व सचिव सुनील मित्रा ने बताया कि चालू वित्त वर्ष में 12 मार्च तक की बढ़ोतरी को आगे भी बरकरार रखा जायेगा। सीआईआई की सालाना रिजनल मीट में मित्रा ने कहा कि मंत्रालय ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के आकलन को संशोधित किया है। अप्रत्यक्ष करों में अब तक 92 फीसदी का संग्रहण अब तक कर लिया गया है और प्रत्यक्ष कर संग्रहण में 79 फीसदी का संग्रहण किया जा चुका है। अब अप्रत्यक्ष कर का संशोधित लक्ष्य तय किया गया है।

होलोग्राम में 19% की तेजी

नई दिल्ली ◆ देश का होलोग्राम उद्योग प्रतिवर्ष 19 फीसदी की दर से बढ़ रहा है। होलोग्राफी को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्री बॉडी होलोग्राम मैन्युफैक्चरर्स एसोसिऐशन ऑफ इंडिया (एचओएमएआई) द्वारा देश में होलोग्राम इंडस्ट्री पर की गई दूसरी वित्तीय अध्ययन में यह बात सामने आई है। एचओएमएआई ने बताया कि भारत में होलोग्राम का बाजार अनुमानत 240 करोड़ रुपये का है जोकि आने वाले वर्षों में 15 फीसदी की दर से बढ़ेगा। ग्राहकों को नकली उत्पादों से बचाने और सुरक्षा देने के साथ ही गुणवत्तापरक सर्विस देने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ रही है। बाहर के देशों को लगातार निर्यात किए जाने से होलोग्राम उद्योग में यह तेजी आई है। **(प्रेट्र/ब्यूरो)**

वृद्धि ◆ कंपनियों की कुल बिक्री में एचडी बॉक्स की बिक्री दहाई अंकों में

डीटीएच कंपनियों को हाई डेफिनेशन से मिली रफ्तार

ब्रॉडकास्टर्स तेजी के साथ एचडी कंटेंट की तरफ रुख कर रहे हैं। ऐसे में एचडी निश्चित तौर पर गेम चेंजर साबित होगा

रक्षित सिंह ◆ नई दिल्ली

KASPERSKY lab World's leading anti-virus software
www.kaspersky.co.in
Scratch and Win! Register online: http://www.sakri.in/howzatt

डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) क्षेत्र में हाई-डेफिनेशन (एचडी) नया गेम चेंजर साबित हो रहा है। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे आयोजनों से देश में एचडी सेट-टॉप-बॉक्स (एसटीबी) की बिक्री को रफ्तार मिल रही है। कंपनियों की कुल बिक्री में एचडी बॉक्स की बिक्री दहाई अंकों में पहुंच चुकी है और आने वाले दिनों में आईपीएल जैसे आयोजनों के दौरान डीटीएच कंपनियों को यह हिस्सेदारी और तेजी के साथ बढ़ने की उम्मीद है।

देश की सबसे बड़ी डीटीएच कंपनी डिश टीवी लिमिटेड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर (सीओओ) सलिल कपूर ने बिजनेस भास्कर को बताया कि वर्ल्ड कप के दौरान एचडी बॉक्स की बिक्री 10 गुना ज्यादा बढ़ गई है। उन्होंने बताया कि फिलहाल कंपनी की रोजाना की बिक्री में एचडी बॉक्स की हिस्सेदारी 7-8 फीसदी है जो आने वाले महीनों के दौरान 10 फीसदी से भी ज्यादा हो जाएगी। कपूर ने कहा कि ब्रॉडकास्टर्स तेजी के साथ एचडी कंटेंट की तरफ रुख कर रहे हैं। ऐसे में एचडी निश्चित तौर पर गेम चेंजर साबित होगा। टाटा स्काई लिमिटेड के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर विक्रम मेहरा ने बताया कि वर्ल्ड कप के दौरान उनकी कंपनी के एचडी डीवीआर को जबरदस्त रेस्पांस मिला है। लेकिन, कंपनी की नीति के हिसाब से उन्होंने कोई भी आंकड़ा देने से इंकार कर दिया। उन्होंने बताया कि कंपनी का डीवीआर 625 घंटों की रिकॉर्डिंग मुहैया करा रहा है जो देश में किसी भी डीटीएच कंपनी के मुकाबले सबसे ज्यादा है। एयरटेल डिजिटल टीवी के डायरेक्टर और सीईओ अजय पुरी ने बताया कि मेट्रो शहरों में कंपनी की कुल बिक्री में एचडी बॉक्स की हिस्सेदारी 15-20 फीसदी है जो आने वाले दिनों में कंटेंट बढ़ने के साथ तेजी के साथ बढ़ेगी।

गेम चेंजर

वर्ल्ड कप के दौरान एचडी बॉक्स की बिक्री 10 गुना ज्यादा बढ़ गई

फिलहाल रोजाना की बिक्री में एचडी बॉक्स की हिस्सेदारी 7-8 फीसदी

एचडी में डीवीआर टाटा स्काई, रिलायंस डिजिटल व वीडियोकॉन में

डिश टीवी और सन डायरेक्ट केवल एचडी बॉक्स मुहैया करा रही है

बात पते की

डीवीआर में लाइव कंटेंट को रिकॉर्ड करने की सुविधा होती है। टाटा स्काई को वर्ल्ड कप के दौरान कंपनी के एचडी डीवीआर को जबरदस्त रेस्पांस मिला है। लेकिन, कंपनी ने नीति के हिसाब से कोई भी आंकड़ा देने से इंकार कर दिया।

गौरतलब है, डीवीआर में लाइव कंटेंट को रिकॉर्ड करने की सुविधा होती है। फिलहाल एचडी में डीवीआर की सुविधा देने वाली कंपनियों में टाटा स्काई, रिलायंस डिजिटल, वीडियोकॉन डी2एच और एयरटेल मुहैया करा रही हैं। डिश टीवी और सन डायरेक्ट केवल एचडी बॉक्स मुहैया करा रही है।

एलएनजी की कीमत बढ़ने की है संभावना

जापान में सुनामी से हजारों की मौत और संपत्तियों का भारी नुकसान हो चुका है

प्रेट्र ◆ नई दिल्ली

8%
है भारत में कुल गैस की मांग में एलएनजी का हिस्सा

जापान में परमाण्विक संकट को देखते हुए एलएनजी की कीमतें कम समय में ज्यादा तेजी का रुख अपना सकती हैं। क्रिसिल ने एक रिपोर्ट में ऐसी आशंका जताई है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल का मानना है कि जापान के ऊर्जा उत्पादन में बाधा आ जाने के कारण ऐसी आशंका है कि एलएनजी की कीमतें बढ़ेंगी। भारत में कुल गैस की मांग में एलएनजी का हिस्सा करीब 8 फीसदी है। इसके उपभोक्ता न केवल शहर में हैं बल्कि कैप्टिव पावर प्लांट और छोटी औद्योगिक इकाई में भी इस गैस की भारी मांग है। इससे ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए भारत को अधिक कीमत अदा करनी पड़ेगी। ऐसी बातें जापान का भूकंप और सुनामी : प्रभाव और विश्लेषण नाम की रिपोर्ट में क्रिसिल ने बताई है।

क्रिसिल की रिपोर्ट के मुताबिक जापान में सुनामी के कारण हजारों लोगों की मौत हो गई है। संपत्तियों का भारी नुकसान हुआ है और जापान के परमाणु प्लांट को भी नुकसान हुआ है। इस कारण से परमाणु प्लांट को बंद करना पड़ा है। जापान में कुल ऊर्जा जरूरतों के 25 फीसदी हिस्से की पूर्ति परमाणु ऊर्जा से होती है। अब जापान को ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए कोयला और एलएनजी पर अधिक जोर देना होगा। उसे कोयला, एलएनजी और पेट्रोलियम पदार्थों का अधिक से अधिक आयात करना होगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जापान में कोयला पर आधारित ऊर्जा प्लांट में 60 फीसदी से अधिक बंद हो गये हैं। ऐसे में ऊर्जा की जरूरतों के मुताबिक उत्पादन नहीं है। ऐसे में एलएनजी की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें जापान के आपदा को देखते हुए तेजी के साथ बढ़ सकती हैं। वैसे भी कीमतें 9 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू से बढ़कर 11-12 एमएमबीटीयू हो चुकी है। ऐसी आशंका है कि आने वाले तीन चार महीनों के दौरान कीमतें 13-14 डॉलर प्रति एएमबीटीयू हो सकती है।

जापान से होने वाली कोयला की मांग में 1 करोड़ 20 लाख टन प्रति साल की बढ़ोतरी हो सकती है। कोयले की इस मांग से इसकी कीमतों पर प्रभाव पड़ने का अनुमान क्रिसिल ने जताया है। क्रिसिल का मानना है कि इससे वर्ष 2011 के दौरान कोयला की कीमतों में 4-5 डॉलर प्रतिटन की बढ़ोतरी हो सकती है।

ऊर्जा

जापान में कुल ऊर्जा जरूरतों के 25 फीसदी हिस्से की पूर्ति परमाणु ऊर्जा से होती है

अब जापान को ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए कोयला व एलएनजी पर अधिक जोर देना होगा

बात पते की

जापान में कोयला पर आधारित ऊर्जा प्लांट में 60 फीसदी से अधिक बंद हो गये हैं। ऐसे में ऊर्जा की जरूरतों के मुताबिक उत्पादन नहीं है।

डायरेक्ट सेलिंग से बड़े पैमाने पर स्व-रोजगार

11वीं
रैंक के साथ शीर्ष डायरेक्ट सेलिंग देशों में है डायरेक्ट सेलर्स की संख्या के लिहाज से भारत

बिजनेस भास्कर ◆ नई दिल्ली

डायरेक्ट सेलिंग बड़े पैमाने पर लोगों खास कर महिलाओं को स्व रोजगार के मौके उपलब्ध करा रही है। आईसीआरआईआर द्वारा डायरेक्ट सेलिंग के सामाजिक-आर्थिक प्रभावः नीतिगत प्रोत्साहन की जरूरत पर जारी की गई रिपोर्ट में यह बात कही गई है।

रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्ट सेलिंग सेक्टर तेज गति से बढ़ रहा है और डायरेक्ट सेलर्स की संख्या भी बढ़ रही है। सेक्टर में बड़े पैमाने पर लोगों को खास कर महिलाओं को रोजगार मुहैया कराने की संभावना और इसके सकारात्मक सामाजिक-आर्थिक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए कोई भी नीतिगत निर्णय लेते समय देश में रोजगार की स्थिति को ध्यान में रखा जाना चाहिए। सर्वे डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों, उनके मैन्यूफैक्चरिंग और सप्लाई चेन एजेंटों, डायरेक्ट सेलर्स, उपभोक्ताओं और नीति निर्माताओं सहित 2500 लोगों की राय पर आधारित है। सर्वे में पाया गया है कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां भारत में मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए निवेश करने के अलावा सप्लाई चेन को मजबूत बना रहीं हैं। ये कंपनियां बड़े पैमाने पर उत्पाद स्थानीय मैन्यूफैक्चरर्स से खरीद रहीं हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2008-2010 के दौरान आर्थिक मंदी के समय में डायरेक्ट सेलर्स की संख्या 4.84% बढ़ी है। डायरेक्ट सेलर्स की संख्या के लिहाज से भारत 11 वीं रैंक के साथ शीर्ष डायरेक्ट सेलिंग देशों में है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक मंदी के दौरान डायरेक्ट सेलिंग ने सेफ्टी नेट मुहैया कराया जिसके कारण बड़ी संख्या में डायरेक्ट सेलर्स सेक्टर से जुड़े। इसके बावजूद सेक्टर की ग्रोथ को रोकने वाली तमाम बाधाएं मौजूद हैं।

इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन (आईडीएसए) के चेयरमैन योगिंद्र सिंह के मुताबिक वैश्विक स्तर पर डायरेक्ट सेलिंग श्रम आधारित उद्योग है और स्व-रोजगार, महिला सशक्तिकरण कौशल विकास के लिहाज से इसका सकारात्मक सामाजिक-आर्थिक प्रभाव है। इसके अलावा डायरेक्ट सेलिंग परिवार में खर्च होने वाली आय बढ़ाने, तकनीकी हस्तांतरण, स्थानीय मैन्यूफैक्चरर्स के लिए सोर्सिंग के मौके मुहैया कराने और लॉजिस्टिक नेटवर्क्स के विकास जैसे आर्थिक लाभ मुहैया कराती है। साथ ही डायरेक्ट सेलिंग की ग्रोथ लॉजिस्टिक्स, मैन्यूफैक्चरिंग और पैकेजिंग जैसे सेक्टरों अप्रत्यक्ष रोजगार के मौके मुहैया कराती है। आईडीएसए के सेक्रेटरी जनरल छवि हेमंथ ने कहा कि सेलिंग से आम आदमी कमाई की क्षमता बढ़ा कर जीवन स्तर को बेहतर बना सकेगा।

बात पते की

डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां भारत में मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए निवेश करने के अलावा सप्लाई चेन को मजबूत बना रहीं हैं। ये कंपनियां बड़े पैमाने पर उत्पाद स्थानीय मैन्यूफैक्चरर्स से खरीद रहीं हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2008-2010 के दौरान आर्थिक मंदी के समय में डायरेक्ट सेलर्स की संख्या 4.84% बढ़ी है।

महंगाई से विकास दर संकट में

मुंबई ◆ देश की बढ़ती विकास दर पर घरेलू और विदेशी स्थितियों का बुरा प्रभाव पड़ने लगा है। भारत में बढ़ती जा रही मुद्रास्फीति और धीमे निवेश के कारण आर्थिक फैलाव में परेशानियां आ रही हैं। इससे ऐसी आशंका है कि आने वाले वित्त वर्ष में विकास दर 9 फीसदी के लक्ष्य से कम रहेगी।

आर्थिक विश्लेषकों के अनुसार एशिया की तीसरी अर्थव्यवस्था में फरवरी के दौरान मुद्रास्फीति 8.3 फीसदी रही जिससे रिजर्व बैंक पर गहरा दबाव बना हुआ है। देश में निवेश की स्थितियां भी बहुत माकूल नहीं हैं। नौकरशाही द्वारा देरी किये जाने के कारण निवेश उतना नहीं हो पा रहा है जितना कि होना चाहिए। मुंबई में मान इंडस्ट्रीज के सीनियर वाइस प्रेसीडेंट केजी मंत्री ने कहा कि आधारभूत संरचना के विकास की जरूरत है। लेकिन अभी भी यह उतना नहीं हो पा रहा है जितना कि होना चाहिए।

दिसंबर को समाप्त हुई तिमाही में देश में निवेश की विकास दर 6 फीसदी रही है। यह सिटी ग्रुप के आकलन के अनुसार बहुत ही कम है जो कि उसने 18 फीसदी की विकास दर का अनुमान लगाया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गुरुवार को ही चेतावनी दी है कि देश में निवेश की स्थितियां बहुत अनुकूल नहीं हो सकती हैं। **(रॉयटर्स)**

पेज 1 का शेष

राहत के लिए प्रीति...

कोर्ट की सलाह पर उनकी कंपनी ने कंपाउंडिंग के लिए आरओसी चंडीगढ़ के जरिए आवेदन किया है। उन्होंने बताया कि उनकी कंपनी ने अक्टूबर 2010 में आरओसी कार्यालय को कंपनी की वित्त वर्ष 2008-09 की बैलेंस शीट के साथ-साथ रिटर्न भी दाखिल कर दिया था। इसके बाद 2009-10 की बैलेंस शीट और रिटर्न भी दाखिल किए जा चुके हैं। इधर, आरओसी डा. राज सिंह का कहना है कि केपीएच ड्रीम्स की कंपाउंडिंग एप्लीकेशन का अध्ययन किए जाने के बाद इसे तकरीबन एक सप्ताह पहले ही कंपाउंडिंग के लिए सीएलबी को भेजा गया है।

गौरतलब है कि कंपनी कानून के उल्लंघन को लेकर आरओसी द्वारा केपीएच ड्रीम्स के खिलाफ अप्रैल 2010 में दायर याचिका पर चंडीगढ़ के सीजेएम कोर्ट ने प्रीति जिंटा, नेस वाडिया, मोहित बर्मन, कर्णपाल और कंपनी के सीईओ अनिल श्रीवास्तव के खिलाफ 24 जुलाई 2010 को वारंट जारी किया था जिस पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने 3 अगस्त 2010 को रोक लगा दी थी।

केपीएच की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर करने वाले वकील डीएस पटवालिया ने याचिका में कंपनी कानून के उल्लंघन को स्वीकार करते हुए कहा है कि कंपनी लॉ बोर्ड में कंपाउंडिंग आवेदन करेगी। केपीएच ड्रीम्स पर आरओसी को बैलेंस शीट और रिटर्न दाखिल न करने का आरोप लगा है। कंपनी ने 2008-09 के लिए रिटर्न के साथ-साथ बैलेंस शीट दाखिल नहीं की है, जबकि कंपनी कानून 1956 के सेक्शन 162 और 168 के तहत हर साल कंपनी का रिटर्न (कंपनी के चेयरमैन व निदेशकों का ब्योरा) और सेक्शन 220 के तहत बैलेंस शीट दाखिल करना अनिवार्य है। सूत्रों के मुताबिक कंपनी ने 2009-10 के रिटर्न के साथ-साथ बैलेंस शीट भी आरओसी कार्यालय को निर्धारित समय पर नहीं भेजी है। इसको लेकर भी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

पीएम के खिलाफ...

इस बीच, प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को कहा कि वेबसाइट 'विकीलीक्स' की केबल में सांसदों को रिश्वत देने का जो आरोप लगाया गया है वह पूरी तरह से गलत है। प्रधानमंत्री ने विपक्षी हमले के दबाव में आए बगैर कहा कि वर्ष 2008 में विश्वास मत के दौरान सांसदों को घूस देने का जो आरोप लगाया गया है उसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि न तो सरकार और न ही कांग्रेस से जुड़े किसी व्यक्ति ने कोई गैर कानूनी काम किया है।

होली में आठ गुना तक बढ़...

दिल्ली से पटना के मार्ग पर भी यही हाल है। इस पर 19 मार्च के लिए सबसे सस्ता टिकट गो एयर का 10381 रुपये का है। फुल सर्विस वाले जेट एयरवेज का टिकट 20479 रुपये का है जो एक महीने पहले चार से पांच हजार रुपये में मिल रहा था। यात्रियों का कहना है कि विमानन कंपनियां मजबूरी का फायदा उठा रही हैं। यहां अकेले रह कर नौकरी करने वाले युवा होली में जरूर घर जाना चाहते हैं, इसी भावना को भुनाया जा रहा है।

इस वेबसाइट पर किसी शहर में कोई मार्ग चुनेंगे तो उस पर प्री पेड आटो या टैक्सी का किराया आ जाएगा

ऑटो-टैक्सी ड्राइवरों की मनमानी से मिलेगी निजात

शिशिर चौरसिया ◆ नई दिल्ली

अनजान शहरों में ऑटो रिक्शा और टैक्सी वालों की अनाप शनाप मांग से तंग हो गए हों तो एक वेबसाइट की मदद से इससे निजात पा सकते हैं। टैक्सीऑटोफेयर डॉट कॉम नाम की इस वेबसाइट पर दिल्ली एवं अन्य महानगरों के साथ साथ अहमदाबाद, अमृतसर, लुधियाना, चंडीगढ़ और जयपुर समेत 18 से भी ज्यादा शहरों की जानकारी है। इसमें फेयर चार्ट के साथ साथ विभिन्न स्थानों के बीच की दूरी की गणना, उस दूरी का भाड़ा और नक्शा भी दिया हुआ है।

वेबसाइट को डेवलप करने वाले पुणे के कंप्यूटर इंजीनियर स्वप्निल शाह ने बिजनेस भास्कर को बताया कि इस वेबसाइट पर किसी शहर में कोई मार्ग चुनेंगे तो उस पर प्री पेड आटो या टैक्सी का किराया आ जाएगा। यही नहीं, उसका मार्ग भी गूगल मैप की सहायता से दिखाया जाएगा ताकि ड्राइवर गलत मार्ग पर घुमाते नहीं रहे। सही-सही किराया है या नहीं, इस पर उनका कहना था कि चार्ट संबंधित शहर के परिवहन विभाग या जिलाधिकारी से लिया गया है। इसके अलावा इस बारे में जो भी अधिसूचना जारी होती है, उसे भी शामिल किया जाता है। सेवा के दायरे में सिर्फ प्रीपेड आटो या टैक्सी ही नहीं, बल्कि इजी कैब, मेगा कैब, मेरू कैब, विंग्स रेडियो कैब जैसे 10 से भी ज्यादा निजी रेडियो टैक्सी सेवा को भी शामिल किया गया है। जिन्हें रेडियो टैक्सी लेना हो, वह विभिन्न कंपनियों के किराये की तुलना करें और जो सस्ता हों, उसे ही चुनें। इसका उपयोग भी आसान होगा, क्योंकि सूचना क्रांति की वजह से अधिकतर युवा या कारोबारी व्यक्ति इंटरनेट की सुविधा वाला मोबाइल हैंडसेट रखते हैं। इस वेबसाइट को मोबाइल पर भी देखा जा सकता है।

इस वेबसाइट को डेवलप करने का विचार कहां से आया, इस पर उनका कहना था कि वह नौकरी के सिलसिले में मुंबई और बेंगलुरू में लगभग रोज इन लोगों की मनमानी के शिकार होते थे। उन्हें एक बार दिल्ली आना पड़ा, तब एक आटो वाले ने हजतरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से आईआईटी ले जाने के लिए दो घंटे तक दिल्ली दर्शन कराया।

इसका पता उन्हें बाद में लगा, तभी इस तरह की एक वेबसाइट बनाने के संकल्प लिया जिसे कुछ महीने में साकार कर दिया। फिलहाल इस वेबसाइट पर दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरू, पुणे, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद, अमृतसर, चंडीगढ़, कोयम्बटूर, जयपुर, कोलकाता, लुधियाना, नागपुर, त्रिवेन्द्रम और पटना शहरों की जानकारी समेटे हुए है। शीघ्र ही इसमें कुछ और टीयर टू सिटीज को शामिल किया जाएगा।

वेबसाइट

गूगल मैप की सहायता से दिखाया जाएगा ताकि ड्राइवर गलत मार्ग पर घुमाते नहीं रहे

अधिकतर कारोबारी इंटरनेट की सुविधा वाले मोबाइल हैंडसेट का करते हैं इस्तेमाल

सुविधा

टैक्सीऑटोफेयर डॉट कॉम नाम की इस वेबसाइट पर दिल्ली व अन्य महानगरों के साथ अहमदाबाद, अमृतसर व जयपुर समेत 18 से भी ज्यादा शहरों की जानकारी है। फेयर चार्ट के साथ विभिन्न स्थानों के बीच की दूरी की गणना, किराया और नक्शा भी दिया हुआ है।

ग्राहकों ने सीडीएमए को नकारा

बिजनेस भास्कर ◆ नई दिल्ली

मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) के शुरुआती आंकड़ों पर गौर किया जाए तो भारतीय मोबाइल ग्राहकों ने सीडीएमए के मुकाबले जीएसएम सेवा प्रदाता कंपनियों को तरजीह दी है। शुरुआती दो महीनों के आंकड़ों पर गौर करें तो वीडियोकॉन, एमटीएनएल, टाटा टेलीसर्विसेज, बीएसएनएल और रिलायंस को ग्राहकों के मोर्चे पर झटका लगा है। इसके अलावा अन्य तकरीबन सभी कंपनियों को एमएनपी के चलते ग्राहक बढ़े हैं।

इसमें वोडाफोन को कुल 1,92,761 ग्राहकों का फायदा हुआ है। आइडिया को 1,50,789 तो एयरटेल को 1,48,215 ग्राहकों का फायदा हुआ है। एयरसेल को 44,842 ग्राहकों का तो यूनीनॉर एमएनपी के चलते 6,330 नए ग्राहक अपने पाले में खींच पाई है।

प्रकाशक एवं मुद्रक अनिल महाजन द्वारा मेसर्स डी बी कॉर्प. लिमिटेड के लिए भास्कर प्रिंटिंग प्रेस 10-11, सेक्टर बी, इंडस्ट्रियल एरिया, गोविंदपुरा, भोपाल (म.प्र.) से मुद्रित एवं 6, द्वारका सदन, प्रेस कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, भोपाल (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक क. यतीश राजावत*। फोन नंबर 0755-3988884 *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार। आरएनआई नं. MPHIN/2008/25612